राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 203

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 31 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

विजडन की टी-20 टीम में कोहली और बुमराह

>> 14

ठंड के साथ कोहरे की मार, दिल्ली में टूटा 119 साल का रिकॉर्ड

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

दिल्ली में शायद ही कोई होगा, जिसने सोमवार जैसी ठिठुरन अपने जीवन में देखी हो। पखवाड़े भर से कंपकंपा देने वाली ठंड ने 119 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिन ही नहीं, बल्कि पूरा दिसंबर माह सन् 1901 के बाद सबसे ठंडा रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से 11 डिग्री नीचे गिरकर 9.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। 1997 में दिसंबर माह में अधिकतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस गया था।

रविवार रात से ही राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की मोटी परत दिखने लगी थी। सोमवार सुबह दृश्यता शून्य हो गई। दिन में भी कोहरे एवं प्रदूषण के मिश्रण से घना स्मॉग छाया रहा। इससे पूरे दिन जबरदस्त ठंड रही। गर्म कपड़े पहनने के बावजूद लोग कांपते रहे। न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री कम 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 97 से 100 फीसद रहा।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मप्र में ग्वालियर व दतिया का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस था। जयपुर में 55 साल बाद एक डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तराखंड में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों समेत कई झीलें जम गई हैं।

आज भी परेशान करेगी सर्दी : प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार को भी सर्दी का प्रकोप ऐसे ही बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार और गुरुवार को बारिश के कारण रात का तापमान बढ़कर 7 से 8 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिन का तापमान 15 से 16 डिग्री के आसपास जा सकता है।

ठंड से उप्र में 62 मरे पेज>>6

- पूरे उत्तर भारत में जनजीवन प्रभावित, रेल और हवाई यातायात बाधित
- 1901 के बाद दिल्ली में रही सबसे लंबी शीतलहर
- जयपुर में 55 साल बाद 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान

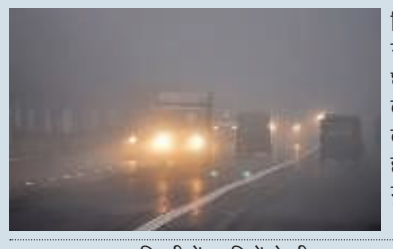

दिल्ली में सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे घने कोहरे से दृश्यता बेहद कम रही। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर गुजरना पड़ा। ध्रुव कुमार

लगातार शीतलहर के हुए 18 दिन

दिल्ली में 18 दिनों से शीतलहर चल रही है, जबकि दिसंबर 1997 में 17 दिन बर्फीली हवाएं चली थी। इस दृष्टि से शीतलहर का भी ऑल टाइम रिकॉर्ड बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1919, 1929, 1961 और 1997 में दिसंबर माह का औसत अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। इस वर्ष अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री पहुंच गया है, जो शुक्रवार तक और नीचे जाएगा।

डायवर्ट करनी पड़ीं 500 उड़ानें

कोहरे के चलते दृश्यता बहुत कम होने से रेल और सड़क यातायात प्रभावित हैं। राजधानी व शताब्दी जैसी ट्रेनें भी घंटों विलंब से चल रही हैं। दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ हवाई अड्डों पर विमान सेवाएं प्रभावित हुईं। दिल्ली में लगभग 500 उड़ानें डायवर्ट करनी पड़ीं।

शहर	न्यूनतम तापमान
श्रीनगर	-6.6
मथुरा	.5
मनाली	-2.8
शिमला	3.6
पिथौरागढ़	1.4
फरीदकोट	0.7
सीकर	0.5
ग्वालियर	2.0
दिल्ली	2.6

(डिग्री सेल्सियस में)

सरोकार

लोहे से लड़ रणजीत ने बदल दी दो पीढ़ियों की तकदीर

गुरदासपुर : जब्बे और हिम्मत की मिसाल हैं पंजाब के गुरदासपुर जिले के छोटे से कस्बे कलानौर की 60 वर्षीय रणजीत कौर। उन्होंने 24 साल पहले पति की मौत के बाद परिवार के सामने खड़ी मुसीबतों को अपने हौसले से बौना साबित कर दिखाया। (पेज-11)

जागरण विशेष

अनसुलझी पहेली! शीला की जुबानी पूरी कहानी...

नई दिल्ली : ओशो का इतिहास पहेली है। मानो रहस्य-रोमांच से भरी कोई अधूरी कहानी। ओशो यानी रजनीश की सबसे करीबी व सबसे विद्रोही शिष्या रहीं मां आनंद शीला की जुबानी वह पूरी कहानी। शीला का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

सतत विकास में केरल अव्वल और बिहार फिसड्डी

नई दिल्ली : नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक-2019 में केरल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जबकि बिहार प्रदर्शन के मामले में फिसड्डी रहा है। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

मप्र के हनी ट्रैप मामले में मंत्रियों के ओएसडी भी शामिल

भोपाल : मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप मामले में दो मंत्रियों के ओएसडी के नाम भी सामने आए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। मानव तस्करी से जुड़े मामले में विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा पेश चालान में ओएसडी हरीश खरे और अरुण निगम के नाम शामिल हैं।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

एसबीआइ ने लोन ग्राहकों को दिया नए साल का तोहफा

मुंबई : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने खुदरा लोन समेत एमएसएमई सेक्टर के ग्राहकों को नए साल का तोहफा दिया है। एसबीआइ ने एक्सटर्नल बेंचमार्क-बेस्ड रेट को 8.05 से घटाकर 7.80 परसेंट प्रतिवर्ष कर दिया है। नई ब्याज दरें बुधवार से प्रभावी होंगी।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

हिजबुल्ला के ठिकानों पर अमेरिकी हमला, 25 की मौत

बगदाद : इराक व सीरिया में कातिब हिजबुल्ला और हिजबुल्ला ब्रिगेड के पांच ठिकानों पर अमेरिकी सेना के हमले में 25 लोग मारे गए और 51 घायल हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा, हमले यह संदेश देने के लिए किए गए हैं कि अमेरिकियों के जीवन को खतरे में डालने वाली ईरान की किसी कार्रवाई को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा।

हथियारों के फर्जी लाइसेंस केस में सीबीआइ की बड़ी कार्रवाई

भ्रष्टाचार पर वार ▶ जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्य में केंद्रीय एजेंसी ने पहली बार की छापेमारी

दो वरिष्ठ आइएएस अफसरों समेत कई राज्यों में 17 ठिकानों की ली तलाशी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और उसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने वहां के प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआइ ने गैरकानूनी तरीके से दूसरे राज्यों के लोगों को हथियारों के लाइसेंस देने के मामले में जम्मू-कश्मीर के आठ जिलों के उपायुक्त या जिलाधिकारियों के ठिकानों समेत कुल 17 स्थानों पर छापा मारा, जिनमें दो आइएएस अधिकारी यशा मुद्गल और कुमार राजीव रंजन शामिल हैं। 2007 बैच की आइएएस अधिकारी मुद्गल फिलहाल जम्मू पॉवर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन की सीएमडी और 2010 बैच के आइएएस अधिकारी राजीव रंजन जम्मू-श्रीनगर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सीईओ हैं।

सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, राज्य प्रशासन की सिफारिश पर पिछले साल अगस्त में इस मामले में दो केस दर्ज किए गए थे और जुलाई महीनेमें मुख्य तौर हथियार बेचने वाले लाइसेंसी दुकानदारों के यहां छापा मारा गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेज बरामद हुए थे। उनकी पड़ताल व जांच के बाद सोमवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुला, उधमपुर, किश्तवार, सोपियां,राजौरी, डोडा, पुलवामा के तत्कालीन उपायुक्तों या जिलाधिकारियों के ठिकानों की तलाशी ली गई। इनमें कश्मीर में तीन, जम्मू में 11 और मोहाली (पंजाब), गुरुग्राम (हरियाणा), और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में एक-एक स्थान शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर से 2012 से 2017 के बीच जारी सभी लाइसेंस की जांच की जा रही है।

दरअसल जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तरीके से हथियार का लाइसेंस दूसरे राज्यों के लोगों को देने के रैकेट को राजस्थान के आतंकरोधी दस्ते (एटीएस) ने उजागर करते हुए नवंबर 2017 में 52 लोगों को गिरफ्तार किया था। एटीएस के अनुसार जम्मू क्षेत्र के डोडा, रामबन और उधमपुर जिले में कुल एक लाख 43 हजार 13 हथियारों के लाइसेंस में से एक लाख 32 हजार 321 लाइसेंस दूसरे राज्यों के लोगों को जारी किए गए थे। पूरे जम्मू-कश्मीर में पिछले एक दशक में जारी चार लाख 29 हजार 301 लाइसेंस में से केवल 10 फीसदी ही राज्य के लोगों को दिए गए थे।

जाहिर है आतंकवाद से ग्रस्त राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से हथियारों के लाइसेंस जारी किए जा रहे थे। इसके बाद राजस्थान के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ओपी गलहोत्रा ने पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराने का अनुरोध किया था। बाद में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल एसपी मलिक ने इसकी जांच सीबीआइ से कराने की सिफारिश की थी। यही नहीं उन्होंने जुलाई 2018 में जनवरी 2017 से लेकर फरवरी 2018 के बीच राज्य से जारी किए गए हथियारों के सभी लाइसेंस को रद कर दिया था। (पेज-सात भी देखें)

फर्जी गन लाइसेंस मामले की जांच कर रही सीबीआइ की टीम सोमवार को जम्मू में सतवारी के अशोक नगर स्थित जम्मू-कश्मीर पॉवर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन (जेकेपीडीसी) कार्यालय में आइएएस अधिकारी यशा मुदगल से पूछताछ करने पहुंची। जागरण

बेटे आदित्य को उद्धव ने बनाया कैबिनेट मंत्री

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार, अजीत पवार फिर बने उप मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र में करीब एक माह पुरानी उद्धव ठाकरे सरकार का सोमवार को पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को कैबिनेट मंत्री बनाया है। महाराष्ट्र में पिता के मुख्यमंत्री रहते पुत्र के मंत्री बनने का यह संभवतः पहला मामला है। राकांपा नेता अजीत पवार ने एक बार फिर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वह रिकॉर्ड चौथी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 26 कैबिनेट एवं 10 राज्य मंत्रियों को राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अजीत पवार ने दो माह के भीतर दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 23 नवंबर को उन्होंने भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस के साथ इस पद की शपथ ली थी। मंत्रिमंडल में आदित्य के अलावा कुछ और युवा चेहरों को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल में तीन महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इनमें से दो को कैबिनेट एवं एक को राज्यमंत्री बनाया गया है। दोपहर एक बजे शुरू हुए शपथ ग्रहण समारोह में राकांपा के 10 कैबिनेट,चार राज्यमंत्री, कांग्रेस के आठ कैबिनेट, दो राज्यमंत्री तथा शिवसेना कोटे से आठ कैबिनेट एवं चार राज्यमंत्रियों ने शपथ ली। शिवसेना ने अपने कोटे में निर्दलीय विधायक शंकरराव गडाख को तथा राज्यमंत्री कोटे में दो निर्दलीय विधायकों बच्चू कडू एवं राजेंद्र यड्रावकर को स्थान दिया है। इस प्रकार ठाकरे मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 43 हो गई है। इनमें 16 राकांपा के, 15 शिवसेना के एवं 12 कांग्रेस के हैं। उद्धव के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय शिवसेना, कांग्रेस एवं राकांपा के दो-दो कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी।

मुंबई में सोमवार को विधान भवन में आयोजित समारोह में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पिता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अभिवादन करते आदित्य ठाकरे। प्रेट्र

भाजपा ने किया बहिष्कार पेज>>4

फेसबुक ने कश्मीर पर पाकिस्तान के फर्जी प्रचार पर लगाई रोक

- सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अब नहीं हो सकेगा पीबीसी की खबरों का सीधा प्रसारण
- प्रसारण मानकों के उल्लंघन को लेकर पीबीसी को पहले भी दी थी चेतावनी

इस्लामाबाद, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर में तेजी से सामान्य होते हालात को देखकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार के लिए वो हर हथकंडा अपना रहा है। सोमवार को उसने फेसबुक के जरिए दुष्प्रचार करना चाहा, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। फेसबुक ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (पीबीसी) की ओर से कश्मीर को लेकर किए जा रहे फर्जी प्रचार के उसके सीधे प्रसारण पर रोक लगा दी। पीबीसी अब इसका रोना रो रहा है।

पीबीसी ने सोमवार को कहा कि कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन, कर्फ्यू और पाबंदी को लेकर रेडियो पाकिस्तान के बुलेटिन के सीधे प्रसारण को फेसबुक प्रशासन ने रोक दिया। पीबीसी ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें फेसबुक की तरफ से मई में उसे चेतावनी दी गई है। फेसबुक ने तब पीबीसी पर प्रसारण मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। पाकिस्तान सरकार की मुख्य प्रवक्ता फिरदौस आशिक अवान ने फेसबुक की तरफ से लगाई गई रोक को मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार फेसबुक पर रेडियो पाकिस्तान की खबरों का दोबारा सीधा प्रसारण शुरू कराने की कोशिश करेगी।

नौसेना में फेसबुक पर पाबंदी पेज>>3

जनरल बिपिन रावत बने देश के पहले सीडीएस

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के तौर पर जनरल बिपिन रावत के नाम पर मुहर लग गई है। सोमवार को सरकार ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को यह पद सृजित करने का एलान किया था और 24 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सीडीएस की भूमिका तीनों सेनाओं और सरकार के बीच समन्वयक की रहेगी। कारगिल युद्ध के बाद से ही इस तरह के पद की मांग उठ रही थी। उस समय रिपोर्टों में यह सामने आया था कि सेनाओं के बीच समन्वय की कमी के कारण युद्ध में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था।

पद सृजित किए जाने के बाद से ही जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस बनाए जाने की चर्चा थी। रविवार को सरकार ने सीडीएस के लिए अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 62 से 65 साल कर दिया था। इसे भी इस पद पर रावत की नियुक्ति से जोड़कर देखा जा रहा था। जनरल रावत सेना प्रमुख के पद से मंगलवार को रिटायर होने जा रहे हैं। 16 मार्च, 1958 को जन्मे बिपिन रावत मार्च, 2020 में 62 साल के हो जाएंगे। सीडीएस पद पर रावत की नियुक्ति की खबर आते ही ट्विटर पर शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, 'जनरल रावत को पहला सीडीएस बनने पर बधाई। सशस्त्र बलों से संबंधित सभी मसलों के प्रधान सैन्य सलाहकार के नए मिशन के लिए मेरी शुभकामनाएं।' भाजपा नेता बैजयंत जय पांडा और कई ट्विटर यूजर्स ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।

- सरकार ने लगाई मुहर, तीनों सेनाओं के समन्वयक के रूप में निभाएंगे भूमिका
- कारगिल युद्ध के समय से ही उठ रही थी इस पद के सृजन को लेकर मांग

नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत। एएनआइ

इसलिए पड़ी जरूरत : युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय सबसे बड़ी चुनौती रहती है। युद्ध के बदलते हालात में देश की सुरक्षा को देखते हुए इस समन्वय की जरूरत और भी बढ़ गई है। सीडीएस की नियुक्ति से इसमें मदद मिलेगी। तीनों सेनाओं को समान गति से बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

यह है प्रस्ताव : सीडीएस की भूमिका रक्षा व इससे जुड़े मामलों में प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री के एकीकृत सलाहकार की होगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय में 'डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स' के नाम से नया विभाग गठित होगा और सीडीएस इसके सचिव होंगे। यह विभाग केवल सैन्य क्षेत्र से जुड़े मामले देखेगा। सीडीएस का उद्देश्य सेनाओं को ट्रेनिंग, स्टाफ व अन्य अभियानों के लिए एकीकृत करना होगा। सरकार को बेहतर सैन्य सुझाव भी मिल सकेंगे।

भूमिका और जिम्मेदारी : सीडीएस की नियुक्ति के बाद भी तीनों सेना प्रमुख विशेष मामलों को लेकर रक्षा मंत्री को सलाह देते रहेंगे। सीडीएस को किसी कमांड के लिए कोई भूमिका नहीं निभानी होगी। सीडीएस रक्षा संपदा परिषद, रक्षा प्लानिंग कमेटी के सदस्य होंगे। वह ऑपरेशन, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, मेंटिनेंस जैसी बातों के लिए तीनों सेनाओं के एकीकरण पर काम करेंगे।

दूर होगा भ्रम

प्रधानमंत्री मोदी ने आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव का वीडियो किया ट्वीट, सद्गुरु ने साझा किया पाक में अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना का अनुभव

सीएए संग भारत, पीएम की अगुआई में भाजपा ने शुरू किया अभियान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर समर्थन जुटाने के लिए भाजपा नेताओं ने सोमवार को सोशल मीडिया पर 'इंडिया सपोर्ट्स सीएए' हैशटैग से अभियान शुरू किया। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव का वीडियो ट्वीट कर सच्चाई सामने रखी। प्रधानमंत्री ने सद्गुरु के वीडियो से नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से सुनने और सच्चाई जानने की अपील की।

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा कि सद्गुरु ने ऐतिहासिक संदर्भों के साथ भाईचारे की हमारी संस्कृति पर शानदार ढंग से प्रकाश डाला है। यही नहीं सद्गुरु ने वीडियो में बताया है कि किस तरह निहित स्वार्थी समूहों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के बारे में गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। दरअसल, सद्गुरु से लखनऊ की एक लड़की ने नागरिकता संशोधन कानून से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने की गुजारिश की थी। इस दौरान सद्गुरु ने बताया कि भारत में हमेशा से सभी धर्मों के लिए समान आदर की परंपरा रही है और किसी के साथ धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया गया। यही नहीं, आजादी के समय धर्म के आधार पर देश का बंटवारा जरूर हो गया, लेकिन भारत ने पंथनिरपेक्षता को स्वीकार किया। जबकि पड़ोसी देश ने इस्लामिक गणतंत्र को स्वीकार किया।

नरेंद्र मोदी फाइल फोटो

वीडियो में सद्गुरु ने अजरबैजान के बाकू मंदिर में पाकिस्तान से आए हिंदुओं के साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि किस तरह वहां कानून के तहत धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनके अनुसार पाकिस्तान से आए एक हिंदू ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा था कि शादी के ढाई साल बाद उसकी पत्नी को जबरन उठाकर ले जाया गया और उसी दिन शाम को धर्म परिवर्तन कर उसका निकाह किसी अन्य मुस्लिम के साथ कर दिया गया। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह व्यक्ति पुलिस या अदालत में कोई शिकायत दर्ज नहीं करा पाया क्योंकि पाकिस्तान में कानूनन सिर्फ इस्लाम के तहत हुए निकाह को मान्यता है, किसी अन्य धर्म के अनुरूप हुई शादी की कानूनी मान्यता ही नहीं है। सद्गुरु ने पड़ोसी देशों में हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध जैसे अल्पसंख्यकों के अलावा अन्य समुदाय के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के आधार पर सीएए में उन्हें भी शामिल करने के तर्क को भी खारिज कर दिया। उनका कहना था कि दुनिया के सभी देशों में कोई न कोई समुदाय इस तरह के आरोप लगाता रहता है, लेकिन हम सभी के लिए नागरिकता के दरवाजे नहीं खोल सकते। यह केवल 2014 तक आने अल्पसंख्यकों तक सीमित है।

सीएए के खिलाफ हो रहे विरोध पर दुख जताते हुए जग्गी वासुदेव ने कहा कि सरकार को भी इतने बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बताया कि किस तरह आम भारतीय मुसलमानों को नागरिकता खत्म हो जाने का भय दिखाया गया जो पूरी तरह से गलत है। साथ ही जग्गी वासुदेव ने बताया कि पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में एनआरसी है। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें रहने वाले सभी नागरिकों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जग्गी वासुदेव के अनुसार सरकार इस मामले में जनता को पूरी जानकारी देने में असफल रही। यह जानकारी दी जानी चाहिए।

कानून पर सियासत (विशेष) पेज>>5

रेलवे भी उपद्रवियों से नुकसान की वसूली की तैयारी में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सीएए विरोध के नाम पर उपद्रवियों ने पहुंचाया 80 करोड़ का नुकसान
- तोड़फोड़ करने वालों पर रेलवे एक्ट की धारा 151 के तहत दर्ज होंगे मुकदमे

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर रेलवे भी सीएए विरोध के नाम पर परिसंपत्तियों का नुकसान करने वाले उपद्रवियों से वसूली करेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद यादव ने इसका एलान किया। उन्होंने कहा कि सीएए का विरोध करने के नाम पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी के जरिये विभिन्न जोनों में 80 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। अब उन्हीं लोगों से वसूली कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। रेलवे अफसरों के अनुसार, इसके लिए उपद्रवियों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 151 के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। रेलवे एक्ट में रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सात साल तक की कैद का प्रावधान है। चूंकि कानून-व्यवस्था राज्यों का विषय है, इसलिए उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए रेलवे को राज्यों की सहमति लेनी होगी। असम में भाजपा सरकार होने के कारण यह आसान होगा, जबकि बंगाल में तृणमूल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख को देखते हुए ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। हालांकि, रेल मंत्री पीयूष गोयल ममता बनर्जी से उपद्रवियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं।

सबसे ज्यादा 70 करोड़ की परिसंपत्तियों का नुकसान पूर्व रेलवे में हुआ है। 10 करोड़ का नुकसान पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में हुआ है। दक्षिण-मध्य रेलवे को हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है।